भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3535
दिनांक 17 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

महाराष्ट्र में दुग्ध उत्पादन

3535. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में भैंस और गाय के दूध का मूल्य निर्धारित करती है;
(ख) महाराष्ट्र राज्य में प्रतिदिन गाय और भैंस का कुल कितना दूध एकत्र किया जाता है;
(ग) महाराष्ट्र राज्य में प्रतिदिन दूध का कितना उत्पादन होता है और वहां इसकी आवश्यकता कितनी है;
(घ) सरकार द्वारा किसानों को दूध का बेहतर मूल्य देने के लिए क्या निर्णय लिया गया है;
(ङ) क्या महाराष्ट्र में दुग्ध उत्पादन आवश्यकता से कम है;
(च) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि देश में बड़ी मात्रा में रसायनों से युक्त कृत्रिम दूध का उत्पादन होता है;
(छ) यदि हां, तो इसका उत्पादन किन-किन कंपनियों और डेयरियों द्वारा किया जाता है और क्या सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं; और
(ज) रसायनों से युक्त कृत्रिम दूध बनाने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार देश में दूध और दूध उत्पादों की खरीद और बिक्री मूल्यों को विनियमित नहीं करता। सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा उनकी उत्पादन लागत और बाजार शक्तियों के आधार पर मूल्य तय किए जाते हैं।

(ख) से (ड.) मूल पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में अनुमानित दूध उत्पादन 160.45 लाख टन अर्थात 439.59 लाख लीटर प्रतिदिन (एलएलपीडी) है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अक्टूबर 2024 माह में दूध की औसत खरीद 171.16 लाख किलोग्राम प्रतिदिन और दूध की औसत बिक्री 145.21 एलएलपीडी थी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि दूध का उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक दूध से अधिक है।

पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण अवसंरचना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को पूरित और संपूरित करने के लिए महाराष्ट्र सहित देश भर में निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)
(ii) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO)
(iii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)
(iv) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)
(v) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)
(vi) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)

ये योजनाएं बोवाइन पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार करने, डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क का विस्तार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने तथा पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रही हैं। ये पहलें दूध उत्पादन की लागत को कम करने और दूध की कीमतों को स्थिर करने में मदद करने के साथ-साथ डेयरी से आय बढ़ाने में भी मदद करती हैं।

(च) से (ज) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने वर्ष 2023 में दूध और दूध उत्पाद निगरानी अभियान चलाया था। जिसमें 36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 756 जिलों को कवर करते हुए दूध के 1605 यादृच्छिक नमूने इकट्ठे किए गए और उनका परीक्षण किया गया। इनमें से किसी भी नमूने में रसायनों जैसे डिटर्जेन्ट, सल्फेट और फार्मेल्डीहाइड की मिलावट नहीं पाई गई। हालांकि केवल 3 नमूनों (0.18%) में मेलामाइन एफएसएसआर द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक था।

1605 नमूनों में से, दूध के 85 नमूने महाराष्ट्र से एकत्रित किए गए थे जिनमें से किसी भी नमूने में रसायनों जैसे मेलामाइन, डिटर्जेन्ट, सल्फेट और फार्मेल्डीहाइड की मिलावट नहीं पाई गई थी।

******